

Weekly One Liners 19th to 25th of January 2026

दावोस 2026: मुख्य तारीखें, थीम, प्रतिभागी और फोकस में वैश्विक चुनौतियाँ

वैश्व आर्थिक मंच (WEF) की वार्षिक बैठक 2026 का आयोजन 19 जनवरी 2026 से दावोस, स्विट्ज़रलैंड में होगा। पाँच दिनों तक चलने वाले इस शिखर सम्मेलन में लगभग 3,000 वैश्विक नेता भाग लेंगे। बैठक में आर्थिक मंदी, भू-राजनीतिक तनाव, जलवायु जोखिम और तकनीकी बदलाव जैसी वैश्विक चुनौतियों के समाधान पर चर्चा की जाएगी। यह सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ रही है और वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव देखने को मिल रहा है।

समाचार में क्यों?

वैश्व आर्थिक मंच (WEF) की वार्षिक बैठक 2026 19 जनवरी से दावोस में शुरू हो रही है। इस वर्ष का सम्मेलन अब तक के सबसे बड़े आयोजनों में से एक है, जिसमें 130 से अधिक देशों के नेता भाग ले रहे हैं।

दावोस और वैश्व आर्थिक मंच क्या हैं?

- वैश्व आर्थिक मंच (WEF) एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है।
- पिछले 50 से अधिक वर्षों से यह मंच सरकारों, व्यवसायों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और नागरिक समाज के नेताओं को एक साथ लाता रहा है।
- इसका सबसे प्रमुख आयोजन दावोस वार्षिक बैठक है, जहाँ सार्वजनिक-निजी सहयोग के माध्यम से वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की जाती है।
- WEF का उद्देश्य संवाद, सहयोग और नीति-नवाचार के ज़रिये दुनिया की स्थिति में सुधार करना है।

दावोस 2026: तिथि, स्थान और थीम

- तिथि: 19 जनवरी से 23 जनवरी 2026
- स्थान: दावोस, स्विट्ज़रलैंड
- थीम: "संवाद की भावना (A Spirit of Dialogue)"

इस वर्ष की थीम एक विभाजित और प्रतिस्पर्धात्मक विश्व में सहयोग की आवश्यकता पर बल देती है। चर्चाओं का केंद्र बिंदु होगा—

- भरोसे का पुनर्निर्माण
- भू-राजनीतिक तनावों का प्रबंधन
- नवाचार आधारित विकास
- आर्थिक विखंडन और तेज़ तकनीकी बदलाव के बीच समावेशी विकास

दावोस 2026 में भाग लेने वाले

- WEF के अनुसार, 130 से अधिक देशों से लगभग 3,000 नेता भाग लेंगे।
- इनमें करीब 400 वरिष्ठ राजनीतिक नेता और लगभग 65 राष्ट्राध्यक्ष/सरकार प्रमुख शामिल होंगे।
- G7 देशों के शीर्ष नेता भी इसमें मौजूद रहेंगे।
- प्रमुख प्रतिभागियों में डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, शामिल हैं।
- संयुक्त राष्ट्र (UN), अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) जैसे वैश्विक संस्थानों के प्रमुख भी भाग लेंगे।

व्यापार और प्रौद्योगिकी नेताओं की भूमिका

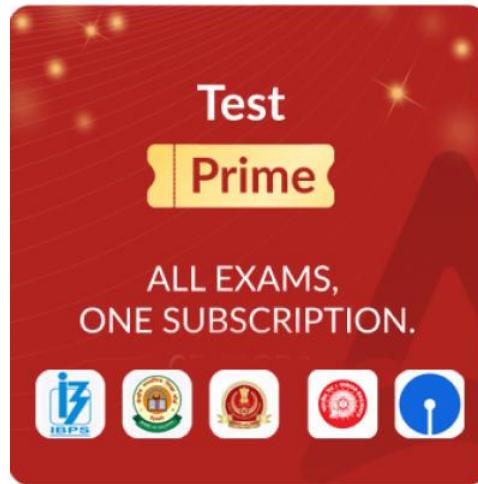
- दावोस 2026 में लगभग 850 शीर्ष CEO और उद्योग जगत के नेता शामिल होंगे।
- सत्या नडेला और जेन्सन हुआंग जैसे प्रमुख तकनीकी नेता भी इसमें भाग लेने की संभावना रखते हैं।
- चर्चाएँ मुख्य रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल परिवर्तन, ऊर्जा संक्रमण, आपूर्ति शृंखलाएँ और नवाचार आधारित विकास पर केंद्रित रहेंगी।
- यह निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है, जो वैश्विक आर्थिक नीतियों को आकार दे रहा है।

दावोस 2026 में भारत की भागीदारी

- भारत का प्रतिनिधित्व एक उच्चस्तरीय राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल करेगा, जो उसकी बढ़ती वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक भूमिका को दर्शाता है।
- वाणिज्य, ऊर्जा, डिजिटल अवसंरचना और विदेश मामलों से जुड़े वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री भाग लेने की उम्मीद है।
- महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और केरल जैसे राज्यों के मुख्यमंत्री भी सम्मेलन में शामिल होंगे।
- टाटा, इंफोसिस, महिंद्रा और JSW जैसे प्रमुख भारतीय उद्योग समूह भारत की मौजूदगी को मजबूत करेंगे।

भारत और राज्यों के उद्देश्य

- भारतीय राज्य दावोस 2026 का उपयोग विदेशी निवेश आकर्षित करने और अपने विकास मॉडल प्रदर्शित करने के लिए करेगा।
- केरल जिम्मेदार निवेश और ESG-आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देगा।
- झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा और समावेशी विकास पर आधारित ऊर्जा संक्रमण मॉडल प्रस्तुत करेगा।
- आंध्र प्रदेश अवसंरचना और उद्योग में निवेश अवसरों को रेखांकित करेगा।
- इन पहलों का उद्देश्य भारत को एक विश्वसनीय वैश्विक विकास साझेदार के रूप में स्थापित करना है।



वैश्विक स्तर पर दावोस 2026 का महत्व

- दावोस 2026 ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया भू-राजनीतिक संघर्षों, आर्थिक सुस्ती, जलवायु संकट और तेज़ तकनीकी बदलाव से जूझ रही है।
- यह मंच उस दौर में संवाद का तटस्थ मंच प्रदान करता है जब बहुपक्षीय सहयोग दबाव में है।
- यहाँ से सतत विकास, जलवायु कार्रवाई, AI शासन और वैश्विक सहयोग पर रणनीतियाँ सामने आने की उम्मीद है, जिससे भविष्य की वैश्विक नीतियों को दिशा मिलेगी।

विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) के बारे में

पहलू	विवरण
स्थापना	1971 में (यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम के रूप में) 1987 में नाम बदलकर विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) किया गया
संस्थापक	क्लॉस श्वाब (Klaus Schwab) - जर्मन अर्थशास्त्री स्टेकहोल्डर कैपिटलिज्म की अवधारणा के प्रवर्तक
मुख्यालय	कोलॉनी (Cologny), स्विटज़रलैंड
उद्देश्य / लक्ष्य	<ul style="list-style-type: none"> दुनिया की स्थिति में सुधार करना सार्वजनिक-निजी सहयोग को बढ़ावा देना वैश्विक आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करना सरकारों, व्यवसायों और नागरिक समाज के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना

UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद की भारत यात्रा के मुख्य नतीजे

भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भारत यात्रा के बाद अपनी रणनीतिक साझेदारी को एक नए स्तर पर पहुँचाया है। इस यात्रा के दौरान निवेश, रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और जन-जन के बीच संपर्क (पीपुल-टू-पीपुल टाईज़) जैसे क्षेत्रों में कई समझौते और महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गईं। ये पहले दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास, आपसी सहयोग और दीर्घकालिक साझेदारी को दर्शाती हैं। भारत-UAE संबंध अब केवल आर्थिक सहयोग तक सीमित न रहकर व्यापक रणनीतिक और बहुआयामी साझेदारी के रूप में उभर रहे हैं।

क्यों चर्चा में?

UAE के राष्ट्रपति ने जनवरी 2026 में भारत का दौरा किया। इस दौरान भारत-UAE रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौता ज्ञापन (MoU), लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) तथा प्रमुख घोषणाओं पर हस्ताक्षर किए गए।

समझौते / MoU / लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) - भारत-UAE

क्रम संख्या	समझौता / MoU / LoI	उद्देश्य
1	गुजरात सरकार (भारत) और निवेश मंत्रालय (UAE) के बीच धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (Dholera SIR) पर LoI	धोलेरा SIR के विकास में UAE की भागीदारी, जिसमें अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, पायलट प्रशिक्षण स्कूल, MRO सुविधा, ग्रीनफिल्ड बंदरगाह, स्मार्ट शहरी टाउनशिप, रेलवे कनेक्टिविटी और ऊर्जा अवसंरचना शामिल
2	IN-SPACe (भारत) और UAE अंतरिक्ष एजेंसी के बीच LoI	अंतरिक्ष उद्योग के विकास और व्यावसायिकरण के लिए संयुक्त अवसंरचना, जैसे प्रक्षेपण परिसर, विनिर्माण क्षेत्र, इनक्यूबेशन केंद्र, प्रशिक्षण संस्थान और विनियम कार्यक्रम
3	भारत और UAE के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी पर LoI	रणनीतिक रक्षा साझेदारी ढाँचे की स्थापना तथा रक्षा उद्योग, नवाचार, उन्नत प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण, विशेष अभियान, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद-रोधी सहयोग का विस्तार
4	HPCL और ADNOC Gas के बीच बिक्री एवं खरीद समझौता (SPA)	वर्ष 2028 से शुरू होकर 10 वर्षों तक HPCL द्वारा ADNOC Gas से 0.5 MMPTA LNG की दीर्घकालिक खरीद
5	APEDA (भारत) और जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण मंत्रालय (UAE) के बीच खाद्य सुरक्षा एवं तकनीकी आवश्यकताओं पर MoU	खाद्य एवं कृषि उत्पादों के व्यापार को सुगम बनाना, भारतीय नियर्ति (विशेषकर चावल) को बढ़ावा देना, भारतीय किसानों को लाभ और UAE की खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करना

घोषणाएँ - भारत-UAE

क्रम संख्या	घोषणा	उद्देश्य
6	भारत में सुपरकंप्यूटिंग क्लस्टर की स्थापना	AI इंडिया मिशन के तहत C-DAC (भारत) और G-42 (UAE) के बीच सहयोग; अनुसंधान, अनुप्रयोग विकास और वाणिज्यिक उपयोग को समर्थन
7	द्विपक्षीय व्यापार को 2032 तक 200 अरब अमेरिकी डॉलर तक दोगुना करना	व्यापार विस्तार, MSME को जोड़ना, भारत मार्ट, वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर और भारत-अफ्रीका सेतु जैसी पहलों के माध्यम से नए बाजारों को बढ़ावा

क्रम संख्या	घोषणा	उद्देश्य
8	द्विपक्षीय नागरिक परमाणु सहयोग को बढ़ावा	उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकियों, बड़े रिएक्टरों, SMRs, रिएक्टर प्रणालियों, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के संचालन, रखरखाव और परमाणु सुरक्षा में SHANTI अधिनियम 2025 के तहत सहयोग
9	गिफ्ट सिटी (गुजरात) में UAE कंपनियाँ - FAB और DP World	FAB द्वारा व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने हेतु शाखा खोलना; DP World द्वारा वैश्विक परिचालनों के लिए जहाज लीजिंग संचालन
10	डिजिटल / डेटा दूतावासों की खोज	परस्पर मान्यता प्राप्त संप्रभुता व्यवस्थाओं के तहत डिजिटल दूतावासों की स्थापना की संभावनाओं का अध्ययन
11	अबू धाबी में 'हाउस ऑफ इंडिया' की स्थापना	भारतीय कला, विरासत और पुरातत्व के संग्रहालय सहित एक सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण
12	युवा आदान-प्रदान को प्रोत्साहन	युवाओं की भागीदारी, शैक्षणिक व अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देना तथा भावी पीढ़ियों के बीच सांस्कृतिक संबंध सुदृढ़ करना

भारत-यूएई संबंधों के बारे में

- भारत और यूएई के बीच व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, प्रवासी संबंधों और टेक्नोलॉजी को मिलाकर एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी है।
- यूएई भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक है और एक प्रमुख निवेशक है।
- ये नतीजे पारंपरिक और उभरते हुए क्षेत्रों में सहयोग को और संस्थागत बनाते हैं।

केंद्र सरकार ने PSGIC, नाबार्ड और RBI के लिए वेतन संशोधन और पेंशन संशोधन को मंजूरी दी

केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों (PSGICs), राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) तथा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन संशोधन और पेंशन संशोधन को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने, सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और वित्तीय क्षेत्र में सामाजिक कल्याण को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

यह फैसला सरकार के सामाजिक सुरक्षा, उचित पारिश्रमिक और पेंशनभोगियों के वित्तीय कल्याण पर निरंतर ध्यान को दर्शाता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिन्होंने देश की आर्थिक और वित्तीय संस्थाओं में दशकों तक सेवा दी है।

क्या-क्या स्वीकृत किया गया है?

सरकारी घोषणा में निम्नलिखित प्रमुख बिंदु शामिल हैं:

- PSGICs के कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन
- NABARD के कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन
- RBI और NABARD के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन संशोधन
- PSGICs के लिए पारिवारिक पेंशन संशोधन

यह निर्णय न केवल लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि यह सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय क्षेत्र सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र मुआवजा और सेवानिवृत्ति लाभ जैसे विषयों से जुड़ा है।

PSGIC कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन

(प्रभावी तिथि: 01 अगस्त 2022)

प्रमुख विवरण

- कुल वेतन बिल में वृद्धि: 12.41%
- मौजूदा मूल वेतन + महंगाई भत्ता (DA) पर वृद्धि: 14%

लाभार्थी

- कुल लाभान्वित कर्मचारी: 43,247 PSGIC कर्मचारी

यह संशोधन कर्मचारियों को महंगाई और बढ़ती जीवन-यापन लागत से निपटने में मदद करेगा।

PSGIC कर्मचारियों के लिए NPS योगदान में वृद्धि

सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में योगदान बढ़ाने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है:

- पहले: 10%
- अब: 14%

किसे लाभ मिलेगा?

- वे कर्मचारी जिन्होंने 01 अप्रैल 2010 के बाद सेवा जाँड़न की है इसका उद्देश्य युवा कर्मचारियों के लिए दीर्घकालिक सेवानिवृत्ति सुरक्षा को मजबूत करना है।

PSGICs के लिए पारिवारिक पेंशन संशोधन

दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को समर्थन देने के लिए पारिवारिक पेंशन ढांचे में बड़ा बदलाव किया गया है।

- संशोधित पारिवारिक पेंशन दर: 30% (एक समान दर)
- प्रभावी तिथि: राजपत्र में अधिसूचना जारी होने की तिथि से

लाभार्थी

- लाभान्वित पारिवारिक पेंशनभोगी: 14,615
- कुल पारिवारिक पेंशनभोगी: 15,582

PSGICs पर वित्तीय भार

- कुल अनुमानित व्यय: ₹8,170.30 करोड़

विवरण:

- वेतन संशोधन बकाया: ₹5,822.68 करोड़
- NPS योगदान वृद्धि: ₹250.15 करोड़
- पारिवारिक पेंशन संशोधन: ₹2,097.47 करोड़

वेतन संशोधन के अंतर्गत शामिल PSGICs

- नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL)
- न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NIACL)
- ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (OICL)
- यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (UIICL)
- जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (GIC)
- एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (AICIL)

NABARD वेतन संशोधन

(प्रभावी तिथि: 01 नवंबर 2022)

प्रमुख विंदु

- वेतन एवं भत्तों में वृद्धि: लगभग 20%
- लागू: ग्रुप A, B और C कर्मचारियों पर

लाभार्थी

- लगभग 3,800 वर्तमान एवं पूर्व कर्मचारी

NABARD पेंशन संशोधन: कौन शामिल?

सरकार ने उन NABARD पेंशनभोगियों के लिए पेंशन संशोधन को मंजूरी दी है:

- जिन्हें मूल रूप से NABARD ने नियुक्त किया था
- जो 01 नवंबर 2017 से पहले सेवानिवृत्त हुए

प्रमुख बदलाव

- उनकी मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन को पूर्व-RBI NABARD पेंशनरों के बराबर किया गया है।

NABARD पर वित्तीय प्रभाव
वेतन संशोधन:

- अतिरिक्त वार्षिक व्यय: लगभग ₹170 करोड़
- कुल बकाया: लगभग ₹510 करोड़

पेंशन संशोधन:

- एकमुश्त बकाया भुगतान: ₹50.82 करोड़
- अतिरिक्त मासिक पेंशन व्यय: ₹3.55 करोड़

लाभार्थी:

- 269 पेंशनभोगी
- 457 पारिवारिक पेंशनभोगी

RBI पेंशन संशोधन

(प्रभावी तिथि: 01 नवंबर 2022)

प्रमुख संशोधन

- पेंशन और पारिवारिक पेंशन में वृद्धि: 10%
- गणना: मूल पेंशन + महंगाई राहत पर 10%

प्रभाव

- मूल पेंशन में प्रभावी वृद्धि: 1.43 गुना

लाभार्थी

- कुल लाभार्थी: 30,769
 - पेंशनभोगी: 22,580
 - पारिवारिक पेंशनभोगी: 8,189

वित्तीय भार

- कुल व्यय: ₹2,696.82 करोड़
 - एकमुश्त बकाया: ₹2,485.02 करोड़
 - वार्षिक आवर्ती व्यय: ₹211.80 करोड़

कुल लाभार्थी (PSGICs + NABARD + RBI)

सरकारी अनुमान के अनुसार:

- लाभान्वित कर्मचारी: लगभग 46,322
- पेंशनभोगी: लगभग 23,570
- पारिवारिक पेंशनभोगी: लगभग 23,260

यह निर्णय हाल के वर्षों में वित्तीय क्षेत्र के लिए सबसे व्यापक वेतन और पेंशन सुधारों में से एक माना जा रहा है।

दावोस 2026: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से मुख्य बातें

विश्व आर्थिक मंच (WEF) की 2026 की वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित की गई, जिसमें लगभग 3,000 वैश्विक नेता शामिल हुए। इनमें राष्ट्रध्यायक, नीति-निर्माता, CEOs, अर्थशास्त्री और नागरिक समाज के प्रतिनिधि शामिल थे। शिखर सम्मेलन का विषय था — “संवाद की भावना (A Spirit of Dialogue)”।

इस बैठक का उद्देश्य ऐसे समय में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना था, जब दुनिया भू-राजनीतिक तनाव, तकनीकी बदलाव और आर्थिक अनिश्चितता से जूझ रही है।

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए दावोस 2026 की चर्चाएँ अंतरराष्ट्रीय संबंध, वैश्विक अर्थव्यवस्था, तकनीकी शासन और बहुपक्षीय सहयोग को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

1. “संवाद की भावना” शिखर सम्मेलन का मूल आधार

- सम्मेलन का केंद्रीय विषय टकराव के बजाय संवाद और सहयोग पर केंद्रित था
- नेताओं ने स्वीकार किया कि दुनिया अधिक ध्रुवीकृत (Polarised) हो रही है
- इसके बावजूद, कूटनीतिक संवाद बनाए रखने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया
- कई सत्रों में बहुपक्षवाद (Multilateralism) पर चर्चा हुई

व्यापार विवाद, सुरक्षा तनाव और तकनीकी शासन जैसे मुद्दों के समाधान के लिए संवाद को सर्वोत्तम साधन माना गया।

यह दर्शाता है कि मतभेदों के बावजूद देश बातचीत के महत्व को समझते हैं।

2. भू-राजनीतिक तनाव चर्चा के केंद्र में

- वैश्विक राजनीति ने दावोस 2026 की चर्चाओं को गहराई से प्रभावित किया
- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भाषण और विदेश नीति रूख पर विशेष ध्यान रहा
- ग्रीनलैंड, टैरिफ (शुल्क) और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा गठबंधनों से जुड़े मुद्दों पर बहस हुई
- कुछ देशों ने मजबूत राष्ट्रीय रणनीतियों का समर्थन किया

वहीं कई देशों ने नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था (Rules-Based Order) के कमज़ोर होने पर चिंता जताई।

नियम-आधारित व्यवस्था से तात्पर्य संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों जैसी प्रणालियों से है, जो देशों के शांतिपूर्ण व्यवहार को निर्देशित करती हैं।

3. कूटनीति के माध्यम से शांति: "बोर्ड ऑफ पीस" पहल

- “बोर्ड ऑफ पीस” नामक एक प्रस्तावित पहल चर्चा में रही
- इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के समाधान के लिए एक संरचित कूटनीतिक मंच बनाना है
- सैन्य टकराव के बजाय संवाद और मध्यस्थता को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है

यह पहल अभी प्रारंभिक चरण में है, लेकिन यह निवारक कूटनीति (**Preventive Diplomacy**) में बढ़ती रुचि को दर्शाती है

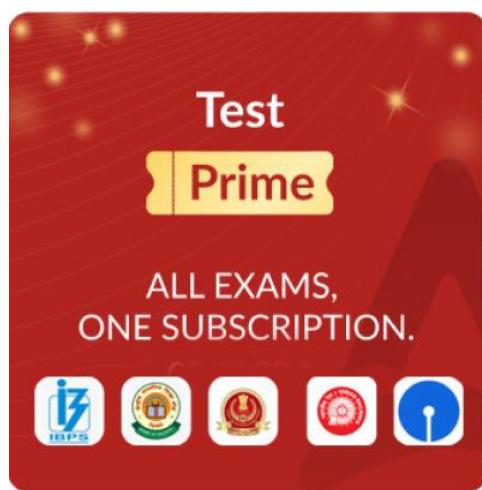
यह विषय परीक्षा में संघर्ष समाधान तंत्र और वैश्विक शांति प्रयासों से जुड़ता है।

4. व्यापार वार्ता और रणनीतिक साझेदारियाँ

- वैश्विक व्यापार संरचना में मौलिक बदलाव हो रहे हैं
- हालिया संकटों के बाद देश आपूर्ति शृंखलाओं को अधिक सुरक्षित और लचीला बना रहे हैं
- EU-भारत आर्थिक सहयोग को व्यापार, तकनीक और हरित ऊर्जा के क्षेत्रों में बढ़ाने के संकेत मिले
- देश किसी एक राष्ट्र या क्षेत्र पर निर्भरता कम करने के लिए रणनीतिक साझेदारियों पर ज़ोर दे रहे हैं
- यह आर्थिक विविधीकरण और रणनीतिक स्वायत्तता की वैश्विक प्रवृत्ति को दर्शाता है।

5. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) भविष्य का प्रमुख विषय

- AI दावों 2026 का सबसे महत्वपूर्ण विषय बनकर उभरा
- इसे आर्थिक विकास, नवाचार और उत्पादकता बढ़ाने वाला माना गया
- साथ ही रोज़गार पर प्रभाव, गलत सूचना, डेटा गोपनीयता और नैतिक जोखिमों पर चिंता जताई गई
- कई देशों ने संतुलित AI नियमन की मांग की
- चर्चा का केंद्र तकनीकी प्रगति और जिम्मेदार शासन के बीच संतुलन रहा
- AI शासन अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े प्रश्नों का प्रमुख विषय है।


6. पुनःकौशल विकास (Reskilling) के माध्यम से कार्यबल परिवर्तन

- WEF की **Reskilling Revolution** पहल को व्यापक समर्थन मिला
- तकनीक-आधारित नौकरी बाज़ार के लिए श्रमिकों को तैयार करने पर ज़ोर दिया गया
- ऑटोमेशन, AI और डिजिटलीकरण के कारण पारंपरिक नौकरियाँ बदल रही हैं
- डिजिटल साक्षरता, आलोचनात्मक सोच और समस्या-समाधान कौशल की माँग बढ़ी है
- सरकारों और निजी क्षेत्र से शिक्षा व कौशल विकास में अधिक निवेश की अपील की गई
- पुनःकौशल विकास को समावेशी और स्थिर आर्थिक विकास के लिए आवश्यक बताया गया।

7. उच्च-स्तरीय वैश्विक भागीदारी

- दावों 2026 में हाल के वर्षों की तुलना में सबसे अधिक राष्ट्राध्यक्षों की भागीदारी रही
- उद्योग जगत के नेताओं ने निवेश और आर्थिक जोखिमों पर चर्चा की
- अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने विकास, जलवायु और वैश्विक शासन पर विचार रखे
- इससे दावों की भूमिका एक प्रमुख वैश्विक नीति मंच के रूप में और मजबूत हुई

हालाँकि, यहाँ लिए गए निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते।

8. व्यापार, विकास और नवाचार पर ज़ोर

- राजनीतिक तनावों के बावजूद दीर्घकालिक आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित रहा
- नवाचार और तकनीक को उत्पादकता बढ़ाने के लिए आवश्यक माना गया
- स्टार्टअप्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक परिवर्तन पर समर्थन जताया गया
- वैश्विक झटकों का सामना कर सकने वाली लचीली अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण पर बल दिया गया
- यह आधुनिक आर्थिक योजना में तकनीक + व्यापार + नीतिगत सुधार के संयोजन को दर्शाता है।

9. जलवायु और सुरक्षा पर भिन्न दृष्टिकोण

- जलवायु परिवर्तन एजेंडा में शामिल रहा, लेकिन पहले की तुलना में कम प्रमुख रहा
- भू-राजनीतिक सुरक्षा और आर्थिक अस्थिरता जैसे तात्कालिक मुद्दे हावी रहे
- फिर भी स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास के महत्व को स्वीकार किया गया
- यह दर्शाता है कि संकट के समय वैश्विक प्राथमिकताएँ बदल सकती हैं
- यह विषय परीक्षा में जलवायु नीति, ऊर्जा सुरक्षा और भू-राजनीति से जुड़ता है।

10. विभाजन से अधिक संवाद, पर चुनौतियाँ बरकरार

- दावोस 2026 ने दिखाया कि वैश्विक नेता अभी भी संवाद और सहभागिता को महत्व देते हैं
- गहरे मतभेदों के बावजूद देशों ने चर्चा में भाग लिया
- सशब्द संघर्ष, आर्थिक असमानता और तकनीकी व्यवधान जैसी समस्याएँ अब भी बनी हुई हैं

शिखर सम्मेलन ने इस बात को रेखांकित किया कि वैश्विक चुनौतियों के प्रबंधन के लिए निरंतर संवाद अनिवार्य है।

National Affairs

- काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट:** PM मोदी ने असम के काजीरंगा के पास 6,957 करोड़ रुपये के एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी, जिसे इस इकोलॉजिकल सेंसिटिव ज़ोन में वाइल्डलाइफ सुरक्षा और हैविटेट प्रोटेक्शन को प्राथमिकता देते हुए कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस:** भारतीय रेलवे ने मालदा रेलवे स्टेशन पर हावड़ा (पश्चिम बंगाल) और गुवाहाटी (असम) के बीच भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च की, जिसमें सेमी-हाई-स्पीड रेल मॉडर्नाइज़ेशन के लिए आधुनिक स्लीपर कोच और अपग्रेड सुविधाएँ हैं।
- राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2026:** PM मोदी ने स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे होने का जश्न मनाया और 5वें राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार (NSA 5.0) लॉन्च किए, जिसमें डीप-टेक इनोवेशन सहित 20 कैटेगरी में टियर-I और टियर-III शहरों के स्टार्टअप को सम्मानित किया गया।
- हिमाचल प्रदेश में MSME टेक्नोलॉजी सेंटर:** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने पंडोगा (ऊना ज़िला) और परवाणू (सोलन ज़िला) में 10 करोड़ रुपये की लागत से दो नए MSME टेक्नोलॉजी सेंटर को मंजूरी दी, जो स्किल डेवलपमेंट और AI और रोबोटिक्स सहित उभरती टेक्नोलॉजी तक पहुंच प्रदान करेंगे।
- SIDBI को 5,000 करोड़ रुपये का इक्विटी इन्फ्यूजन मिला:** केंद्रीय कैबिनेट ने MSMEs के लिए क्रेडिट उपलब्धता बढ़ाने और पूरे भारत में रोजगार सृजन को सपोर्ट करने के लिए SIDBI को तीन किस्तों (FY26-FY28) में 5,000 करोड़ रुपये की इक्विटी सहायता को मंजूरी दी।
- ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन की तैनाती:** केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने मिशन मौसम चरण II के तहत 200 ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन (दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे में प्रत्येक 50) की तैनाती की घोषणा की, ताकि हाई-रिज़ॉल्यूशन शहरी मौसम डेटा और अत्यधिक घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी की जा सके।
- भारत का पहला ओपन-सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट:** केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने और फिनफिश की खेती और समुद्री शैवाल की खेती के ज़रिए तटीय आजीविका पैदा करने के लिए अंडमान सागर में नॉर्थ बे, श्री विजया पुरम में भारत का पहला ओपन-सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया।

- प्रोजेक्ट डॉल्फिन का दूसरा सर्वे लॉन्च:** केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने डॉल्फिन की आवादी का अनुमान लगाने और ताज़े पानी के इकोसिस्टम की निगरानी को मज़बूत करने के लिए गंगा बेसिन सहित प्रमुख नदी प्रणालियों को कवर करते हुए प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वे लॉन्च किया।
- भारत ने अपनी पहली इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट मैन्यूफैक्चरिंग फैसिलिटी शुरू करके अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में एक बड़ा कदम उठाया है।** गुजरात के सानंद में खोरज में इसकी आधारशिला रखी गई, जो देश के बढ़ते अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नया अध्याय है। यह डेवलपमेंट भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को मज़बूत करने में प्राइवेट कंपनियों की बढ़ती भूमिका को दिखाता है।
- यह नई फैसिलिटी अङ्गिस्टा स्पेस द्वारा स्थापित की जा रही है और यह सैटेलाइट और हाई-एंड इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल पेलोड बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी।** पालमनारो नाम का यह प्लांट एक ही छत के नीचे एंड-टू-एंड सैटेलाइट मैन्यूफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह भारत को आयात पर निर्भरता कम करने और अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में स्थानीय इनोवेशन को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

States in the News

- पश्चिम बंगाल हेल्थकेयर पहल:** वर्ल्ड बैंक ने पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम के लिए 286 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग को मंजूरी दी है, जिसका लक्ष्य 90 मिलियन से ज्यादा लोगों को क्लालिटी हेल्थकेयर सेवाओं तक समान पहुंच के ज़रिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता और जीवन प्रत्याशा प्रदान करना है।
- आंध्र प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट:** AP के CM एन. चंद्रबाबू नायडू ने काकीनाडा में दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया प्रोजेक्ट की नींव रखी, जिसमें 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश और 3 चरणों में 1.5 MTPA की क्षमता होगी, जो भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को सपोर्ट करेगा।
- PM मोदी का पश्चिम बंगाल और असम दौरा:** PM मोदी ने मालदा का दौरा किया और 3,250 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शामिल है, और 4 प्रमुख रेलवे परियोजनाओं की नींव रखी, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को मज़बूत करेंगी।
- कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको-सेंसिटिव ज़ोन घोषित किया गया:** केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कुंभलगढ़ WLS के आसपास शून्य से एक किमी के क्षेत्र को इको-सेंसिटिव ज़ोन घोषित किया है, जो समृद्ध जैव विविधता की रक्षा के लिए 243 किमी में फैले 94 गांवों में खनन, औद्योगिक इकाइयों, ईंट भट्टों और बड़े निर्माण पर प्रतिबंध लगाएगा।
- MP डिजिटल गवर्नेंस के साथ भाषिनी:** डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन और मध्य प्रदेश सरकार ने AI-पार्क भाषा टूल और ट्रांसलेशन API को राज्य के डिजिटल प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करने के लिए MoU साझा किया, ताकि मल्टीलिंगुअल डिजिटल गवर्नेंस के ज़रिए कई भारतीय भाषाओं में पब्लिक सर्विस तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

- ओडिशा-मेघालय ECCED सहयोग: ओडिशा और मेघालय की सरकारों ने भुवनेश्वर में अर्ली चाइल्डहुड केयर, एजुकेशन और डेवलपमेंट में सहयोग बढ़ाने के लिए MoU साइन किया, जिसमें समग्र बचपन के हस्तक्षेप के लिए आपसी सीखने और बेस्ट प्रैक्टिस के आदान-प्रदान पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- असम रिसर्च स्कॉलर सपोर्ट स्कीम: असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा ने 'अटल विचार अग्रगामी असम' योजना की घोषणा की, जिसके तहत रिसर्च स्कॉलर्स को 25,000 रुपये प्रति माह और दिव्यांग स्कॉलर्स को 40,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे ताकि रिसर्च, इनोवेशन और एकेडमिक टैलेंट डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके।
- 86वां अधिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन: उत्तर प्रदेश ने 19-21 जनवरी तक 86वें AIPOC 2026 की मेजबानी की, जिसका विषय "मज़बूत विधानमंडल-समृद्ध राष्ट्र" था और इसमें 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 36 पीठासीन अधिकारियों ने भाग लिया और गवर्नेंस, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक परंपराओं पर छह मुख्य प्रस्तावों को अपनाया।
- राजस्थान अलवर में एक नए बायोलॉजिकल पार्क के साथ अपने वाइल्डलाइफ टूरिज्म में एक बड़ा आकर्षण जोड़ने जा रहा है। खूबसूरत काटी धाटी इलाके में प्लान किया गया यह पार्क वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन, जानवरों की देखभाल और टूरिज्म को एक ही जगह पर जोड़ेगा। पूरा होने के बाद, यह नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में अपनी तरह का पहला बायोलॉजिकल पार्क बन जाएगा, जो सफारी, एक रेस्क्यू सेंटर और एक मॉर्डन वेटनरी हॉस्पिटल देगा। प्रस्तावित बायोलॉजिकल पार्क अलवर जिले में काटी धाटी और जयसमंद के बीच डेवलप किया जाएगा। यह लगभग 100 हेक्टेयर ज़मीन में फैला होगा। लगभग 30 प्रतिशत ऐरिया जानवरों के लिए चिडियाघर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि बाकी 70 प्रतिशत को नेचुरल माहौल बनाए रखने के लिए ग्रीन स्पेस के तौर पर रखा जाएगा।
- गोवा सरकार ने हाल ही में राज्य में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट कम्प्युनिकेशंस के साथ एक ज़रूरी समझौता किया है। इस पार्टनरशिप का मकसद गोवा में नागरिकों, पब्लिक सेवाओं और ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तक तेज़, भरोसेमंद और ज़्यादा डिजिटल पहुंच बनाना है।
- उत्तराखण्ड सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में हेल्थकेयर सुविधाओं को मज़बूत करने के लिए एक ज़रूरी कदम उठाया है। गुरुवार को राज्य सरकार ने 'स्वस्थ सीमा अभियान' नाम की एक नई पहल के तहत भारत-तिव्वत सीमा पुलिस (ITBP) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर साइन किए। इस समझौते का मकसद दूरदराज के सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों को बेहतर मेडिकल सेवाएं देना है। MoU पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में उनके आवास पर साइन किए गए। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा भी मौजूद थे। उत्तराखण्ड सरकार और ITBP दोनों के सीनियर अधिकारी भी साइन सेरेमनी में शामिल हुए।

International Affairs

- भारत-यूएई रणनीतिक रक्षा साझेदारी: भारत और यूएई ने द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान एक रक्षा आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिससे एक रणनीतिक रक्षा साझेदारी बनी, जो विशेष अभियानों, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा पर केंद्रित है।
- दुनिया की पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी हाई सीज़ संधि 17 जनवरी, 2026 को लागू हुई। यह समझौता राष्ट्रीय सीमाओं से परे महासागरों की रक्षा के लिए वैश्विक नियम निर्धारित करता है। ये अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र ग्रह के लगभग आधे हिस्से को कवर करते हैं। इस संधि को अत्यधिक मछली पकड़ने, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और गहरे समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र के खतरों से निपटने के लिए एक ऐतिहासिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। 60 से अधिक देशों द्वारा अनुसमर्थन के बाद हाई सीज़ संधि आधिकारिक तौर पर लागू हो गई है। यह अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र, जिसे हाई सीज़ के नाम से भी जाना जाता है, में समुद्री जीवन के संरक्षण के लिए वैश्विक नियम स्थापित करती है।
- युगांडा में एक बहुप्रतीक्षित राष्ट्रपति चुनाव निर्णायक परिणाम के साथ संपन्न हुआ है। अनुभवी नेता योवेरी मुसेवेनी को सातवें कार्यकाल के लिए विजेता घोषित किया गया है। हालांकि, परिणामों ने विवाद खड़ा कर दिया है क्योंकि मुख्य विपक्षी उम्मीदवार ने अनियमिताओं, इंटरनेट बंद होने और मतदान एजेंटों के कथित उत्पीड़न का हवाला देते हुए परिणाम को खारिज कर दिया है। इस चुनाव ने एक बार फिर युगांडा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को वैश्विक जांच के दायरे में ला दिया है।
- फिलीपींस एक नए प्राकृतिक खतरे का सामना कर रहा है क्योंकि ट्रॉपिकल तूफान नोकेन मेयोन ज्वालामुखी के पास लाहार लाने की धमकी दे रहा है। उम्मीद है कि तूफान दक्षिणी लूज़ोन में भारी बारिश लाएगा, जिससे ज्वालामुखी की अशांति से पहले से प्रभावित इलाकों में कीचड़ वाले ज्वालामुखी प्रवाह की चिंता बढ़ गई है। अधिकारियों ने निवासियों से सतर्क रहने और सुरक्षा सलाह का बारीकी से पालन करने का आग्रह किया है।
- भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने अपने आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मज़बूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के दौरान, दोनों देशों ने 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 200 बिलियन डॉलर करने पर सहमति व्यक्त की। इस बैठक के परिणामस्वरूप रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्रों में कई समझौते भी हुए, जो भारत-यूएई साझेदारी के गहराने को दर्शाते हैं।
- 2025 में चीन की आबादी में 3 मिलियन की गिरावट आई। नए बच्चे पालने के प्रोत्साहन के बावजूद जन्म दर रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई।
- चीन एक बढ़ती हुई जनसांख्यिकीय चुनौती का सामना कर रहा है। नए आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि 2025 में चीन की आबादी में फिर से गिरावट आई, जो लगातार चौथे वर्ष संकुचन का संकेत है, भले ही सरकार ने परिवारों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और नीतिगत उपाय शुरू किए हों।

- नुम्बियो द्वारा जारी एक इंटरनेशनल सेफटी रैंकिंग में अबू धाबी को लगातार 10वें साल दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है, जो सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता के लिए इसकी ग्लोबल प्रतिष्ठा की पुष्टि करता है।
- वैज्ञानिकों ने पुष्टि की कि सूर्य ने लेवल-4 सौर विकिरण तूफान को ट्रिगर किया, जो अक्टूबर 2003 के बाद से देखा गया सबसे शक्तिशाली तूफान है। इस तूफान के कारण यूरोप में चमकीले ऑरोरा दिखाई दिए और सैटेलाइट, एविएशन, अंतरिक्ष यात्रियों और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलर्ट जारी किए गए।
- इज़राइल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने पर सहमति जताकर एक महत्वपूर्ण राजनयिक कदम उठाया है, जो गाजा युद्धविराम और युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण की देखरेख के लिए एक प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। इज़राइली प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा घोषित इस फैसले ने इज़राइल की पिछली आपत्तियों से एक बदलाव का सकेत दिया है और राजनीतिक और वैश्विक प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने पुष्टि की है कि इज़राइल डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा प्रस्तावित और जिसकी अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होगा। इस बोर्ड का उद्देश्य गाजा युद्धविराम और भविष्य की शासन व्यवस्था की निगरानी करना है।
- भारत और नामीबिया ने 19-20 जनवरी, 2026 को विदेश कार्यालय परामर्श (FOC) का पांचवां दौर आयोजित किया, जहां दोनों पक्षों ने रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों के साथ-साथ अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने पर सहमति व्यक्त की।
- भारत ने कावुल को 7.5 टन जीवन रक्षक कैंसर दवाएं पहुंचाई हैं, जो मानवीय चिकित्सा सहायता के माध्यम से अफगानिस्तान के लोगों का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

Agreements/MoUs Signed

- C-DAC और G-42 सुपरकंप्यूटिंग क्लस्टर: भारत और UAE ने एडवांस्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और इनोवेशन के लिए सुपरकंप्यूटिंग क्लस्टर स्थापित करने के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) और G-42 के बीच सहयोग पर सहमति जताई।
- IN-SPACe और UAE स्पेस एजेंसी: इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर (IN-SPACe) और UAE स्पेस एजेंसी के बीच लॉन्च सुविधाओं, टेक ज्ञान और स्टार्ट-अप इनक्यूबेशन सहित संयुक्त अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।
- HPCL-ADNOC LNG समझौता: 10-वर्षीय बिक्री और खरीद समझौते से HPCL को 2028 से ADNOC गैस से प्रति वर्ष 0.5 मिलियन टन (MTPA) लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) आयात करने में मदद मिलेगी, जिसका मूल्य USD 2.5-3 बिलियन है।
- APEDA-UAE खाद्य व्यापार MoU: APEDA (MoC&I) और UAE जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण मंत्रालय के बीच खाद्य क्षेत्र व्यापार को बढ़ाने और द्विपक्षीय कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन।

- GeM और WTC मुंबई MSME साझेदारी: गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) और MVIRDC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई ने वैश्विक पहुंच, क्षमता निर्माण और स्थायी खरीद के लिए AI एकीकरण के माध्यम से सार्वजनिक खरीद में MSME भागीदारी को मजबूत करने के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए।
- DIBD-सर्वे ऑफ इंडिया स्थलाकृति डिजिटलीकरण: डिजिटल इंडिया भागीदारी डिवीजन और सर्वे ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2022 के अनुपालन में AI-आधारित भाषण और भाषा प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पूरे भारत में 16 लाख (1.6 मिलियन) से अधिक भौगोलिक स्थानों के नामों को डिजिटाइज़ करने के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए।
- SBI और तमिलनाडु PSUs समझौता: भारतीय स्टेट बैंक ने तमिलनाडु सरकार के साथ एक MoU साझन किया है ताकि TN के राज्य पब्लिक सेक्टर अंडरटेक्निंग्स के कर्मचारियों को ज़ीरो-बैलेंस अकाउंट, रियायती व्याज दरें और प्रीमियम बैंकिंग सपोर्ट के साथ बेहतर कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज के फायदे दिए जा सकें।
- GeM-WCF महिला उद्यमी साझेदारी: GeM और वुमेन्स कलेक्टिव फोरम (WCF) ने महिला उद्यमियों के लिए संस्थागत सहायता को मजबूत करने के लिए एक MoU साझन किया है, जिसमें ऑनबोर्डिंग, कंप्लायांस, प्रोडक्ट लिस्टिंग और ट्रेनिंग पर ध्यान दिया जाएगा, जिसमें 2 लाख महिला-नेतृत्व वाली MSEs रजिस्टर्ड हैं और 80,000 करोड़ रुपये के पब्लिक ऑर्डर हैं।
- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने इंडिया स्किल्स एक्सीलरेटर लॉन्च करके व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास में सहयोग को गहरा करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

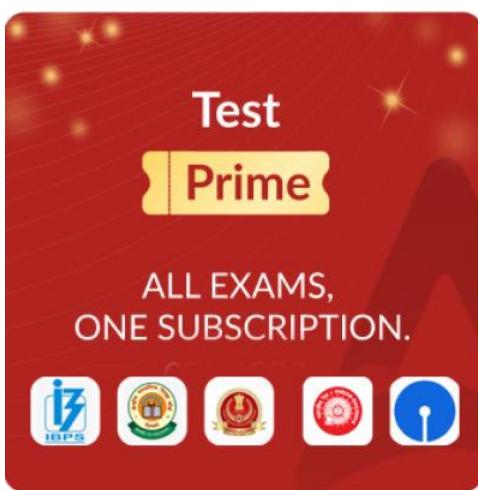
Books and Authors

- पलानीवेलु GUTS का हिंदी एडिशन लॉन्च: उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने जाने-माने सर्जन डॉ. सी. पलानीवेलु की आत्मकथा 'पलानीवेलु GUTS' का हिंदी एडिशन लॉन्च किया, जिसमें लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी में उनके इनोवेशन के सफर और साधारण शुरुआत से लेकर सफलता तक की यात्रा को दिखाया गया है।
- 'चैलिस ऑफ एम्ब्रोसिया' किताब लॉन्च: उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने डॉ. सुरेंद्र कुमार पचौरी (1968 बैच के रिटायर्ड IAS अधिकारी) द्वारा लिखी किताब 'चैलिस ऑफ एम्ब्रोसिया: राम जन्मभूमि- चुनौती और प्रतिक्रिया' लॉन्च की, जिसमें ऐतिहासिक, कानूनी और सांस्कृतिक संदर्भों को मिलाकर लंबे और जटिल राम जन्मभूमि आंदोलन का वर्णन किया गया है।

Banking/Economy/Business News

- पिरामल फाइनेंस को USD 350 मिलियन मिले: पिरामल फाइनेंस लिमिटेड को IFC (USD 200 मिलियन) और ADB (USD 150 मिलियन) से सस्टेनेबल फाइनेंस फ्रेमवर्क के तहत 5 साल की अवधि के लिए USD 350 मिलियन की मल्टीलेटरल फंडिंग मिली, जिसका लक्ष्य टियर 2-3 शहरों में किफायती आवास, SMEs और महिला कर्जदार हैं।

- RBI लोकपाल योजना 2026 जारी: भारतीय रिजर्व बैंक ने 'रिजर्व बैंक – इंटीग्रेटेड लोकपाल योजना (RB-IOS) 2026' जारी की, जो 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी होगी। इसमें कोई विवाद सीमा नहीं है और कई पुरानी योजनाओं को बदलकर परिणामी नुकसान के लिए 30 लाख रुपये तक और समय/उत्पीड़न के लिए 3 लाख रुपये तक का बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाएगा।
- विकिपीडिया ने AI ट्रेनिंग के लिए टेक दिग्गजों के साथ साझेदारी की: विकिमीडिया फाउंडेशन ने अमेज़न, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, मिस्ट्रल AI और परलेक्सिटी के साथ रणनीतिक साझेदारी की है, जो विकिमीडिया एंटरप्राइज कार्यक्रम के माध्यम से LLMs और चैटबॉट के विकास का समर्थन करने के लिए AI ट्रेनिंग के लिए विकिपीडिया सामग्री तक संरचित, सशुल्क पहुंच प्रदान करता है।
- IMF ने भारत के विकास दृष्टिकोण को बढ़ाकर 7.3% किया: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अक्टूबर 2025 में भारत के FY 2025-26 के विकास दृष्टिकोण को 6.6% से बढ़ाकर 7.3% कर दिया है, जो मजबूत कॉर्पोरेट कमाई और मजबूत Q4 गति को दर्शाता है, जबकि FY27-FY28 के लिए अनुमान 6.4% तक कम हो गया है।
- SBI लाइफ ने स्मार्ट प्लैटिना एडवांटेज प्लान लॉन्च किया: SBI लाइफ इंश्योरेंस ने 'स्मार्ट प्लैटिना एडवांटेज' इंडिविजुअल नॉन-लिंक्ड सेविंग्स प्लान लॉन्च किया है, जिसमें 7-10 साल का लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म और फ्लैक्सिवल मैच्योरिटी ऑप्शन (15, 20, 30 साल) हैं। यह प्लान 50,000 रुपये के सालाना प्रीमियम से शुरू होकर गारंटीड एंडिंग्स और कॉम्प्रिहेंसिव लाइफ कवर देता है।
- मूडीज़ ने FY26 में भारत की GDP ग्रोथ 7.3% रहने का अनुमान लगाया: ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने FY26 में भारत की GDP ग्रोथ 7.3% रहने का अनुमान लगाया है, जो FY25 के 6.5% से ज्यादा है। इसके साथ ही इंश्योरेंस सेक्टर में भी मजबूत ग्रोथ का अनुमान है, जिसमें अप्रैल-नवंबर FY26 के दौरान कुल प्रीमियम में 17% की बढ़ोत्तरी के साथ यह 10.9 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
- केनरा बैंक ने केनरा aiPe ऐप में UPI को इंटीग्रेट किया: केनरा बैंक ने NPCI BHIM सर्विसेज लिमिटेड (NBSL) के साथ पार्टनरशिप करके अपने बैंकिंग ऐप केनरा aiPe में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया है। इसके साथ ही यह सुरक्षित डिजिटल पेमेंट्स के लिए NBSL के प्लगइन-बेस्ड UPI सॉल्यूशन को अपनाने वाला पहला बैंक बन गया है।



- एयर इंडिया-सिंगापुर एयरलाइंस कमर्शियल एग्रीमेंट: एयर इंडिया और सिंगापुर एयरलाइंस ने पार्टनरशिप को और मजबूत करने के लिए एक कमर्शियल कोऑपरेशन फ्रेमवर्क पर साझन किए हैं। इसमें इंटीग्रेटेड बुकिंग, बढ़े हुए रूट्स और कोऑर्डिनेटेड फ्लाइट शेड्यूल शामिल हैं, जिससे एयरलाइंस के बीच बिना किसी रुकावट के यात्रा संभव होगी और 61 डेस्टिनेशंस तक कोडशेयर नेटवर्क का विस्तार होगा।
- ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2026: इंफोसिस दुनिया का तीसरा सबसे बैल्यूएवल IT सर्विसेज ब्रांड बन गया है, जिसकी बैल्यू USD 16.4 बिलियन है और ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स स्कोर 86.8/100 है। यह एक्सेंचर (पहला, USD 42.2 बिलियन) और TCS (दूसरा, USD 21.2 बिलियन) के बाद है, जिसने पिछले 6 सालों में 15% CAGR हासिल किया है।
- BSNL और Viasat की नेवी सैटकॉम के लिए पार्टनरशिप: भारत संचार निगम लिमिटेड और Viasat Inc. ने भारतीय नौसेना के सैटेलाइट कम्युनिकेशंस (सैटकॉम) अपग्रेड को सपोर्ट करने के लिए पार्टनरशिप की घोषणा की है, जिसमें Viasat Ka-बैंड सिस्टम को BSNL के L-बैंड नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा और इंस्टॉलेशन जनवरी 2026 के आखिर में होने वाला है।
- RBI ने FEDAI को सेल्फ-रेगुलेटरी ऑर्गनाइजेशन के तौर पर मान्यता दी: भारतीय रिजर्व बैंक ने फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FEDAI) को सभी ऑथराइज्ड डीलर्स के लिए ओमनीबस SRO फ्रेमवर्क के तहत सेल्फ-रेगुलेटरी ऑर्गनाइजेशन (SRO) के तौर पर औपचारिक रूप से मान्यता दी है, जिसमें गवर्नेंस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक साल का ट्रांज़िशन परियड दिया गया है।
- RBI ने जापान के SMBC की पूरी तरह से मालिकाना हक वाली सब्सिडियरी को मंजूरी दी: भारतीय रिजर्व बैंक ने सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन (SMBC) को RBI गाइडलाइंस 2025 के तहत भारत में पूरी तरह से मालिकाना हक वाली सब्सिडियरी (WOS) स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है, जिसमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 22(1) के तहत बैंकिंग लाइसेंस शामिल है।
- Payoneer India को PA-CB लाइसेंस मिला: RBI ने Payoneer India को पेमेंट एग्रीगेटर – क्रॉस बॉर्डर (PA-CB) के तौर पर काम करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है, जिससे भारतीय इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के लिए प्रति ट्रांज़ैक्शन 25 लाख रुपये की लिमिट के साथ क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट ट्रांज़ैक्शन संभव होंगे।
- ZET को RuPay कार्ड पर UPI के लिए NPCI की मंजूरी मिली: क्रेडिट फिनेटेक ZET को थर्ड-पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर (TPAP) के तौर पर काम करने के लिए NPCI की मंजूरी मिल गई है, जिसने ZET UPI लॉन्च किया है, जिससे RBL बैंक के साथ बैंकिंग पार्टनरशिप और Juspay टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से RuPay क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके UPI पेमेंट किए जा सकेंगे।
- RBI ने एक्सपोर्ट-इंपोर्ट के लिए FEMA नियम जारी किए: RBI ने FEMA के तहत 'फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट (माल और सेवाओं का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट) रेगुलेशन 2026' जारी किया है, जो 1 अक्टूबर, 2026 से लागू होगा, जिसमें ट्रेड से जुड़े फॉरेन एक्सचेंज ट्रांज़ैक्शन के लिए एक समान टाइमलाइन और बेहतर मॉनिटरिंग की ज़रूरतें पेश की गई हैं।

- एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए ब्याज सबवेंशन पर RBI के दिशानिर्देश: RBI ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन (EPM) - NIRYAT PROTSAHAN के तहत प्री और पोस्ट-शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट पर ब्याज सबवेंशन के लिए ऑपरेशनल दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिससे MSME एक्सपोर्टर्स को कम क्रेडिट लागत के ज़रिए फायदा होगा।
- टाटा ग्रुप ने महाराष्ट्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर से जुड़ी सेवाओं पर फोकस करते हुए एक वर्ल्ड-क्लास इनोवेशन सिटी बनाने के लिए **11 बिलियन डॉलर** के निवेश की घोषणा की है।
- भारत ने काबुल को **7.5 टन** जीवन रक्षक कैंसर की दवाएं भेजी हैं, जो मानवीय चिकित्सा सहायता के माध्यम से अफगानिस्तान के लोगों का समर्थन करने की अपनी प्रतिवद्धता की पुष्टि करता है।
- भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए, क्रेडिट-फोकस्ड फिनटेक कंपनी **ZET** को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) से थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर (TPAP) के रूप में काम करने की मंजूरी मिल गई है। यह मंजूरी ZET को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सेवाएं देने की अनुमति देती है और UPI के साथ क्रेडिट कार्ड फंक्शनैलिटी को इंटीग्रेट करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
- भारत के फिनटेक खेत्र ने एक और बड़ा कदम आगे बढ़ाया है, क्योंकि फिनटेक डिग्गज रेजरपे की ऑफलाइन पेमेंट डिविजन रेजरपे POS को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर (PA-P) के रूप में काम करने की अनुमति मिल गई है। यह मंजूरी रेजरपे को अपनी इन-स्टोर पेमेंट सेवाओं का विस्तार करने और देश के तेजी से बढ़ते डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में अपनी स्थिति मजबूत करने की अनुमति देती है।
- भारत के क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट इकोसिस्टम के लिए एक बड़े डेवलपर्मेंट में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने **Payoneer India Private Limited** को पेमेंट एग्रीगेटर - क्रॉस बॉर्डर (PA-CB) के रूप में काम करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी Payoneer को ग्लोबल ट्रेड में लगी भारतीय कंपनियों के लिए अंतरराष्ट्रीय पेमेंट ट्रांजैक्शन को आसान बनाने की अनुमति देती है।
- अपनी डिजिटल बैंकिंग क्षमताओं को मजबूत करने के लिए, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने AI-पावर्ड वीडियो KYC (VKYC) सॉल्यूशन को लागू करने के लिए हाइपरवर्ज के साथ पार्टनरशिप की है। इस सहयोग का मकसद बैंक की कस्टमर ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को आधुनिक बनाना है, साथ ही मजबूत रेगुलेटरी कंप्लायांस और डेटा सिक्योरिटी भी सुनिश्चित करना है।
- एडवांस्ड VKYC टेक्नोलॉजी को अपनाने से एफिशिएंसी में सुधार, कस्टमर अनुभव बेहतर होने और बैंक की डिजिटल ग्रोथ स्ट्रेटेजी को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन (EPM) के तहत प्री- और पोस्ट-शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट पर इंटरेस्ट सबवेंशन बढ़ाने के लिए ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी की हैं, खासकर इसके पहले कंपोनेंट, नियर्ता प्रोत्साहन के तहत। इस पहल का मुख्य लक्ष्य MSME एक्सपोर्टर्स के लिए उधार लेने की लागत को कम करके किफायती रूपये एक्सपोर्ट क्रेडिट तक पहुंच में सुधार करना है। इस कदम से भारत के एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को मजबूत होने और छोटे व्यवसायों की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने की उम्मीद है।

- रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (**RXIL**), जो भारत का पहला ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (**TReDS**) प्लेटफॉर्म है, ने अपने शेयरों पर **21.6%** का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। यह एक ऐतिहासिक कदम है क्योंकि RXIL भारत में पहला TReDS प्लेटफॉर्म बन गया है जो अपने स्टेक्होल्डर्स को कैपिटल लौटा रहा है, जो प्लेटफॉर्म की मैच्योरिटी, मजबूत फाइनेंशियल हेल्थ और MSMEs को सपोर्ट करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

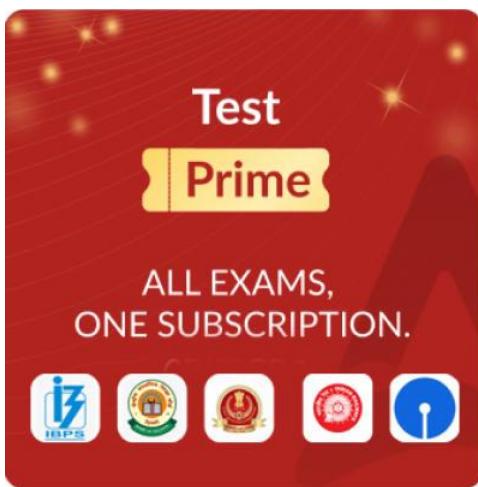
Appointments/Resignations

- प्रवीण वशिष्ठ CVC विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त: राष्ट्रपति द्वौपदी मुर्मू ने विहार कैडर के 1991 बैच के IPS अधिकारी प्रवीण वशिष्ठ को 30 से ज्यादा सालों के लाँ एनकोर्समेंट अनुभव के साथ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (CVC) में 4 साल के लिए या 65 साल की उम्र तक विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किया है।
- ICICI बैंक ने संदीप बछरी को MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया: ICICI बैंक ने संदीप बछरी को 3 अक्टूबर, 2028 तक मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया है, जो अक्टूबर 2018 से उनके पिछले कार्यकाल के साथ नेतृत्व में स्थिरता को दर्शाता है और बोर्ड ने अजय कुमार गुप्ता को नवंबर 2028 तक ED के रूप में फिर से नियुक्त किया है।
- NIA, BSF, ITBP के लिए नए DG नियुक्त: कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राकेश अग्रवाल को DG NIA (31 अगस्त, 2028 तक), प्रवीण कुमार को DG BSF (30 सितंबर, 2030 तक), और शत्रुजीत सिंह कपूर को DG ITBP (31 अक्टूबर, 2026 तक) नियुक्त करने की मंजूरी दी है, जिससे केंद्रीय सुरक्षा बलों के नेतृत्व को मजबूती मिलेगी।
- शिया मुहसिन मोहम्मद अल-ज़िंदानी यमन के PM नियुक्त: यमन की राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद ने शिया मुहसिन मोहम्मद अल-ज़िंदानी को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, जो सलेम बिन बैक की जगह लेंगे। उनके पास उप विदेश मंत्री और कई देशों में राजदूत के रूप में पिछले पदों सहित व्यापक राजनयिक अनुभव है।
- आर्यन वार्ष्ण्य भारत के 92वें शतरंज GM बने: दिल्ली के 21 साल के आर्यन वार्ष्ण्य आर्मेनिया में 16वां आंद्रानिक मार्गर्यन मेमोरियल खिताब जीतकर भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। यह उनकी तीसरी और आखिरी GM नॉर्म थी, जिससे वह दिल्ली के 8वें ग्रैंडमास्टर बन गए हैं।
- दीपेंद्र गोयल ने एटर्नल ग्रुप के CEO पद से इस्तीफा दिया: दीपेंद्र गोयल ने एटर्नल लिमिटेड (जोसेटो और ब्लिंकिट की पेरेंट कंपनी) के CEO और MD पद से 1 फरवरी, 2026 से इस्तीफा दे दिया है। ब्लिंकिट के CEO अलबिंदर सिंह ढाँडसा को उनका उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि गोयल बोर्ड के वाइस चेयरमैन बने रहेंगे।
- टाटा कम्युनिकेशंस ने गणेश लक्ष्मीनारायणन को MD और CEO नियुक्त किया: टाटा कम्युनिकेशंस ने गणेश लक्ष्मीनारायणन (एयरटेल विजनेस के पूर्व कार्यकारी, जिन्हें 30 से ज्यादा सालों का अनुभव है) को नया MD और CEO नियुक्त करने की घोषणा की है। वह ए.एस. लक्ष्मीनारायणन की जगह लेंगे, जो 13 अप्रैल, 2026 को रिटायर हो रहे हैं। गणेश के पास टेलीकॉम और B2B में मजबूत विशेषज्ञता है।

- योवेरी मुसेवेनी युगांडा के राष्ट्रपति फिर से चुने गए: युगांडा के चुनाव आयोग ने घोषणा की कि 81 साल के मौजूदा राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने 71.65% वोट शेयर के साथ जीत हासिल की है और सातवां कार्यकाल (2026-2031) हासिल किया है। विपक्षी नेता बॉबी वाइन को 24.72% वोट मिले। वह 1986 से सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले अफ्रीकी नेता हैं।
- विजेंदर सिंह एशियाई मुक्केबाजी परिषद में नियुक्त: बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भारत के ओलंपिक पदक विजेता विजेंदर सिंह को एशियाई मुक्केबाजी परिषद (ABCO) के सदस्य के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। यह नियुक्ति 2008 बीजिंग ओलंपिक में उनके एतिहासिक कांस्य पदक और मुक्केबाजी में उनके योगदान को देखते हुए की गई है।

Defence News

- भारत फोर्ज को 300 करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट मिले: भारत फोर्ज लिमिटेड के एयरोस्पेस डिवीजन को इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट-VI (EP-VI) फ्रेमवर्क के तहत भारतीय सेना और नौसेना को ओमेगा वन, ओमेगा नाइन ऐसआर ड्रोन और बेयोनेट/क्लीवर लॉइटरिंग म्यूनिशन सहित स्वदेशी मानवरहित सिस्टम की सप्लाई के लिए 300 करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट मिले।
- रक्षा मंत्री ने गोला-बारूद सुविधा का उद्घाटन किया: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागपुर में सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड (SDAL) में मीडियम कैलिवर गोला-बारूद मैन्युफैक्चरिंग सुविधा का उद्घाटन किया, जो भारतीय सेना और नौसेना द्वारा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने वाले 30mm गोला-बारूद का निर्माण करती है। उन्होंने पिनाका रॉकेट सुविधा की समीक्षा की और आर्मेनिया के लिए गाइडेड पिनाका रॉकेट के पहले बैच को हरी झंडी दिखाई।
- INS सागरध्वनि को सागर मैत्री V पहल के लिए रखाना किया गया: भारत के समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत INS सागरध्वनि को कोच्चि से सागर मैत्री पहल के 5वें संस्करण के लिए रखाना किया गया, जो 8 हिंद महासागर रिस देशों (ओमान, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, म्यांमार) के बीच वैज्ञानिक सहयोग और महासागर अनुसंधान को बढ़ावा देता है।



- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल चौहान ने मिलिट्री क्लांटम मिशन पॉलिसी फ्रेमवर्क जारी किया, जो एक विस्तृत योजना है जो बताती है कि सशस्त्र बलों में क्लांटम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। यह दस्तावेज़ पॉलिसी मार्गदर्शन और कार्यान्वयन के लिए चरण-दर-चरण रोडमैप दोनों प्रदान करता है। इसका उद्देश्य अत्याधुनिक वैज्ञानिक नवाचारों का उपयोग करके भारत के रक्षा बलों को भविष्य के लिए तैयार करना है।

Awards and Recognitions

- साइना नेहवाल ने संन्यास की घोषणा की: भारतीय बैडमिंटन दिग्गज साइना नेहवाल ने 21 साल के शानदार करियर के बाद प्रतिस्पृशी बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की। वह वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता (2012 लंदन) थीं, जिन्होंने महिला बैडमिंटन को लोकप्रिय बनाने में एक स्थायी विरासत छोड़ी है।
- विदर्भ ने पहली विजय हजारे ट्रॉफी जीती: विदर्भ क्रिकेट टीम ने बैंगलुरु में BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फाइनल में सौराष्ट्र को 38 रनों से हराकर पहली विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 जीती। अर्थर तायडे ने 128 रन बनाए और अमन मोखाडे ने 814 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता।
- शांति, निरन्तरीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 मोज़ाम्बिक की जानी-मानी मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्राका माचेल को दिया गया है। यह घोषणा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट ने की। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पोषण, महिला सशक्तिकरण और मानवीय सहायता, खासकर मुश्किल और संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में, सुधार के लिए उनके आजीवन प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। इंदिरा गांधी पुरस्कार भारत के सबसे सम्मानित अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है। यह उन व्यक्तियों या संगठनों को मान्यता देता है जिन्होंने शांति, विकास और सामाजिक न्याय में उत्कृष्ट योगदान दिया है। इस पुरस्कार में ₹1 करोड़ पुरस्कार, एक ट्रॉफी और एक प्रशस्ति पत्र शामिल है।

Summits and Conferences News

- 28वां कॉमनवेल्थ स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित: भारत ने 14-16 जनवरी को संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में 42 कॉमनवेल्थ देशों के 61 स्पीकर्स के साथ स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों (CSPOC) का 28वां कॉन्फ्रेंस होस्ट किया और 2028 में लंदन में होने वाले 29वें CSPOC के लिए अध्यक्षता UK के लिंडसे होयल को सौंपी गई।
- वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस 2026: PM मोदी ने 11-15 जनवरी को राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस 2026 का उद्घाटन किया, जिसमें निवेश की प्रतिबद्धताएं शामिल हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का निवेश दोगुना होकर 7 लाख करोड़ रुपये, अदानी ग्रुप का 1.50 लाख करोड़ रुपये का निवेश और सौराष्ट्र और कच्छ के अर्थिक विकास के लिए 5.78 लाख करोड़ रुपये के 5,492 MoU।

- राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस: 19 जनवरी, 2026 को 21वां NDRF स्थापना दिवस मनाया गया, जो 19 जनवरी, 2006 को NDRF की स्थापना की याद में था, जिसमें PM मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शुभकामनाएं दीं और NDRF ने मानवीय सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को उजागर करते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया।
- नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल, भारत रंग महोत्सव (BRM) 2026 के 25वें एडिशन की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। 27 जनवरी से 20 फरवरी 2026 तक होने वाला यह एडिशन भारत के इतिहास में थिएटर का सबसे ज्यादा समावेशी और बड़ा सेलिब्रेशन होने का बादा करता है। इस साल, BRM 2026 पूरे भारत में 40 जगहों पर आयोजित किया जाएगा, जिससे थिएटर बड़े शहरों और दूरदराज के इलाकों तक पहुँचेगा। पहली बार, सातों महाद्वीपों में से हर एक का प्रतिनिधित्व कम से कम एक इंटरनेशनल प्रोडक्शन द्वारा किया जाएगा, जिससे यह सचमुच एक ग्लोबल इवेंट बन जाएगा।

Ranks and Reports

- रिस्पॉन्सिवल नेशंस इंडेक्स 2026 जारी: पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में पहले रिस्पॉन्सिवल नेशंस इंडेक्स (RNI) को लॉन्च किया, जिसमें भारत 0.551513 स्कोर के साथ फ्रांस, अल्बानिया, पोलैंड से आगे 16वें स्थान पर रहा, जबकि सिंगापुर 0.61945 के साथ टॉप पर रहा, उसके बाद स्विट्जरलैंड (0.58692) दूसरे स्थान पर रहा।
- एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 जारी: डेज्ञान शिरा एंड एसोसिएट्स ने एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 जारी किया, जिसमें दिखाया गया कि भारत 11 एशियाई देशों में 6वें स्थान पर बना हुआ है, जिसमें चीन पहले, मलेशिया दूसरे और वियतनाम तीसरे स्थान पर है, जो भारतीय मैन्युफैक्चरिंग में मजबूत सुधारों और तेजी से अग्रल की जरूरत को उजागर करता है।
- WEF ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 21वां ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट संस्करण प्रकाशित किया, जिसमें भू-आर्थिक टकराव को शीर्ष वैश्विक खतरे के रूप में पहचाना गया, इसके बाद राज्य-आधारित संघर्ष, अत्यधिक मौसम, सामाजिक सुरक्षा में कमी, गलत सूचना शामिल है, जिसमें भारत को साइबर असुरक्षा एक बड़े जोखिम के रूप में सामना करना पड़ रहा है।
- NITI आयोग की ग्रीन ट्रांजिशन पर रिपोर्ट: NITI आयोग ने सीमेंट, एल्यूमीनियम और MSME क्षेत्रों के लिए तीन डीकार्बोनाइजेशन रोडमैप जारी किए, जिनका लक्ष्य कार्बन तीव्रता को कम करना और 2070 तक नेट ज़ीरो के लक्ष्य के अनुरूप ग्रीन टेक्नोलॉजी को अपनाना है।

Sports News

- आर्यन वार्ण्य 92वें भारतीय शतरंज GM बने: दिल्ली के 21 वर्षीय आर्यन वार्ण्य आर्मेनिया में 16वां आंद्रानिक मार्गर्यन मेमोरियल खिताब जीतकर भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए। उन्होंने 8 में से 6.5 अंक हासिल करके तीसरा और अंतिम GM नॉर्म हासिल किया।

- विजेंदर सिंह को एशियन बॉक्सिंग काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया गया है। उनके शामिल होने से एशियाई बॉक्सिंग गवर्नेंस में भारत का प्रतिनिधित्व मजबूत हुआ है।
- विदर्भ ने अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब जीता। उन्होंने बंगलुरु में खेले गए फाइनल में सौराष्ट्र को 38 रनों से हराया।
- भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 2026 सीज़न से शुरू होने वाली इंडियन प्रीमियर लीग के लिए जेमिनी के साथ ₹270 करोड़ का स्पॉन्सरशिप समझौता किया है।
- राष्ट्रीय पैरालंपिक पावरलिफ्टिंग चैम्पियनशिप का उद्घाटन जनवरी 2026 में पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस आयोजन ने राष्ट्रीय स्तर पर समावेशी खेलों और दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण पर प्रकाश डाला।
- साइना नेहवाल ने घुटने की गंभीर चोटों, जिसमें कार्टिलेज डिजनरेशन और गठिया शामिल हैं, के कारण लगभग दो साल तक निष्क्रिय रहने के बाद प्रतिस्पर्धी बैडमिंटन से संन्यास की पुष्टि की है।

Schemes and Committees News

- अटल पेंशन योजना को FY 2030-31 तक बढ़ाया गया: केंद्रीय कैबिनेट ने 8.66 करोड़ सब्सक्राइबर वाली APY को जारी रखने की मंजूरी दी, जिससे असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को 60 साल की उम्र के बाद 1,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति माह की गारंटीड पेंशन मिलेगी, साथ ही प्रमोशनल और गैप फंडिंग गतिविधियों के लिए सरकारी फंडिंग सोर्ट भी बढ़ाया गया है।
- MSME सेक्टर कन्वर्जेंस पर नीति आयोग की रिपोर्ट: नीति आयोग ने "योजनाओं के कन्वर्जेंस के माध्यम से MSME सेक्टर में दक्षता हासिल करना" शीर्षक से एक व्यापक रिपोर्ट जारी की, जिसमें 18 ओवरलैपिंग MSME योजनाओं को संबोधित करने और दोहराव को कम करने के लिए सूचना और प्रक्रिया कन्वर्जेंस के दोहरे दृष्टिकोण की सिफारिश की गई है।
- अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 2026: 86वां AIPOC 19-21 जनवरी को लखनऊ में आयोजित हुआ, जिसमें 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 36 पीठासीन अधिकारियों ने भाग लिया और विकसित भारत 2047, विधायी बैठकों, प्रौद्योगिकी एकीकरण और क्षमता निर्माण पर छह प्रस्तावों को अपनाया।
- परिपूर्ण मेडिकलेम आयुष बीमा लॉन्च: वित्त मंत्रालय के तहत DFS ने CGHS लाभार्थियों के लिए 10-20 लाख रुपये के बीमा राशि वाली एक वैकल्पिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है और अधिकतम किफायती बनाने के लिए प्रीमियम पर कोई GST नहीं लगाया जाएगा।
- अटल पेंशन योजना 2030-31 तक बढ़ाई गई: केंद्रीय कैबिनेट ने 8.66 करोड़ सब्सक्राइबर वाली APY को जारी रखने की मंजूरी दी है, जो असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 1,000-5,000 रुपये की गारंटीड मासिक पेंशन सुनिश्चित करती है।

- भारत ने जलवायु कार्रवाई और औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जनवरी 2026 में, सरकार ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS) के तहत अतिरिक्त कार्बन-गहन क्षेत्रों के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता (GEI) लक्ष्य अधिसूचित किए। यह निर्णय भारतीय कार्बन बाजार के क्वरेज का विस्तार करता है और स्थायी आर्थिक विकास का समर्थन करते हुए उत्सर्जन को कम करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।
- सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित एक छोटी बचत योजना है। यह माता-पिता या कानूनी अभिभावकों को 10 साल से कम उम्र की लड़की के नाम पर खाता खोलने की अनुमति देती है। यह योजना आकर्षक व्याज दरें, टैक्स-फ्री रिटर्न और लंबी निवेश अवधि प्रदान करती है, जो इसे लंबी अवधि की वित्तीय योजना के लिए आदर्श बनाती है।
- पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना नाम की एक बड़ी स्वास्थ्य योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, राज्य के हर परिवार को ₹10 लाख तक का मुफ्त और कैशलेस मेडिकल इलाज मिलेगा। इसका मकसद सभी निवासियों को अस्पताल के खर्च की चिंता किए बिना अच्छी क्लालिटी की स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है। इस योजना को आधिकारिक तौर पर मोहाली में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने AAP के राष्ट्रीय संयोजक अर्विंद केजरीवाल के साथ लॉन्च किया। दोनों नेताओं ने कहा कि यह योजना पंजाब की स्वास्थ्य प्रणाली में एक बड़ा बदलाव लाएगी और सभी आय समूहों के लोगों की मदद करेगी।

Science and Technology News

- लक्ष्यद्वीप में क्रस्टेशियन की नई प्रजाति खोजी गई: कुसैट के शोधकर्ताओं ने लक्ष्यद्वीप के कवरती लैगून में 'इंडियाफोटो विजॉय' नाम की एक नई प्रजाति और सूक्ष्म हार्पेकिटकॉइड कोपेपॉड की खोज की है, जिसका शरीर अर्ध-बेलनाकार और एंटीना जैसे अंग हैं। यह खोज अंतरराष्ट्रीय जर्नल जूटैक्सा में प्रकाशित हुई है।
- चींटी मक्की की दो नई प्रजातियाँ खोजी गईः शोधकर्ताओं ने दिल्ली के नॉर्दर्न रिज जंगल और सिरुवानी पहाड़ियों में क्रमशः 'मेटाडॉन घोरपड़ेई' और 'मेटाडॉन रीमरी' नाम की चींटी मक्की की दो नई दुर्लभ प्रजातियों की खोज की है, जो 100 से अधिक वर्षों में पहली खोज है और शहरी वन क्षेत्रों की सुरक्षा के महत्व को दर्शाती है।
- IIT दिल्ली में रेगुलेटरी अफेयर्स के लिए CoE का उद्घाटन: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने IIT दिल्ली में पावर सेक्टर में रेगुलेटरी अफेयर्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया, जिसे CERC और ग्रिड इंडिया के साथ मिलकर भारत के विजली क्षेत्र में रेगुलेटरी रिसर्च और क्षमता निर्माण को मजबूत करने के लिए स्थापित किया गया है।
- केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्टील स्लैग-आधारित सङ्कृत तकनीक को तेजी से अपनाने की सिफारिश की है, खासकर हिमालयी राज्यों में, इसके सिद्ध लाभों और सीमित वर्तमान उपयोग का हवाला देते हुए।

- NASA ने 15 जनवरी 2026 को ISS से पहला मेडिकल इवेक्यूएशन सफलतापूर्वक पूरा किया। SpaceX Crew-11 मिशन समय से पहले लौट आया ताकि पृथ्वी पर एडवास्ड मेडिकल केयर मिल सके, भले ही ऑर्बिट में एस्ट्रोनॉट की हालत स्थिर थी। स्पेसफ्लाइट के लिए एक ऐतिहासिक पल में, NASA ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) से पहली बार मेडिकल इवेक्यूएशन किया। 15 जनवरी 2026 को, एक एस्ट्रोनॉट को एक गैर-गंभीर मेडिकल समस्या होने के बाद SpaceX Crew-11 मिशन को छोटा कर दिया गया। कू सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आया, जो स्पेस हेल्परेकर और एस्ट्रोनॉट सुरक्षा में एक बड़ा मील का पथर है।
- NASA मानव अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक ऐतिहासिक लॉन्च के लिए तैयार है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी आर्टेमिस II को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जो एक ऐतिहासिक मिशन है जो 50 से ज्यादा सालों में पहली बार एस्ट्रोनॉट्स को चंद्रमा के चारों ओर भेजेगा। यह मिशन इसलिए भी खास है क्योंकि दुनिया भर के लोग अपने नाम स्पेसक्राफ्ट में चंद्रमा पर भेज सकते हैं, जिससे यह मिशन विश्व स्तर पर प्रतीकात्मक और प्रेरणादायक बन जाता है। NASA ने केनेडी स्पेस सेंटर में लॉन्च पैड पर आर्टेमिस II रॉकेट का रोलआउट पूरा कर लिया है। यह एस्ट्रोनॉट्स को एक ऐसे मिशन पर लॉन्च करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो इंसानों को पहले से कहीं ज्यादा पृथ्वी से दूर ले जाएगा।

Important Days News

- राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2026 - 16 जनवरी: भारत ने स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे होने का जश्न मनाया, जिसमें PM मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप संस्थापकों को संबोधित किया और 20 श्रेणियों में 5वें राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार (NSA 5.0) और राज्य सुधार फ्रेमवर्क (SRF 5.0) के परिणाम जारी किए।
- भारतीय सेना दिवस 2026 - 15 जनवरी: 78वां भारतीय सेना दिवस राजस्थान के जयपुर में महल रोड पर एक भव्य परेड के साथ मनाया गया (पहली बार नई दिल्ली और सैन्य छावनी के बाहर), जिसमें 30 से अधिक टुकड़ियों, 7 प्रमुख मार्चिंग इकाइयों और नेपाल सेना बैंड की भागीदारी के साथ नई गठित भैरव बटालियन शामिल थीं।
- राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस 2026 - 19 जनवरी: 21वां NDRF स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें दुनिया के सबसे बड़े आपदा प्रतिक्रिया बल की स्थापना की याद में PM मोदी और केंद्रीय मंत्री ने शुभकामनाएं दीं और मानवीय प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
- पराक्रम दिवस 2026 शुक्रवार, 23 जनवरी को मनाया जाएगा। यह दिन पूरे देश में देशभक्ति कार्यक्रमों और शैक्षिक गतिविधियों के साथ मनाया जाएगा। यह तारीख हर साल वही रहती है, क्योंकि यह नेताजी की जयंती से जुड़ी है।
- भारत में हर साल 24 जनवरी को लड़कियों के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य और ओवरऑल भलाई के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। यह दिन लड़कियों के लिए समान अवसर बनाने और समाज में उनके सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने के महत्व पर ज़ोर देता है। यह नागरिकों को याद दिलाता है कि एक मजबूत और प्रगतिशील राष्ट्र बनाने के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना ज़रूरी है।

- बेहतर, ज्यादा समान दुनिया बनाने में शिक्षा की बदलाव लाने वाली शक्ति को पहचानने के लिए हर साल 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। यह दिन इस बात पर ज़ोर देता है कि शिक्षा सिर्फ़ एक सेवा नहीं है, बल्कि एक मौलिक मानवाधिकार और सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का एक मुख्य चालक है।
- पूरे भारत में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 2026 में, यह दिन रविवार, 25 जनवरी को पड़ेगा। यह तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत के चुनाव आयोग (ECI) का स्थापना दिवस है, जो देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ज़िम्मेदार संवैधानिक निकाय है।
- भारत में हर साल 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है, ताकि देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट में टूरिज्म के महत्व को पहचाना जा सके। टूरिज्म सिर्फ़ घूमने-फ़िरने और आराम करने के बारे में नहीं है - यह इकॉनमी को बढ़ावा देने, विरासत को बचाने और कल्चरल एक्स्चेंज को बढ़ावा देने में भी अहम भूमिका निभाता है। यह दिन लोगों को भारत की रिच डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए प्रोत्साहित करता है, साथ ही ज़िम्मेदार और स्टेनेबल ट्रैवल तरीकों को भी बढ़ावा देता है।

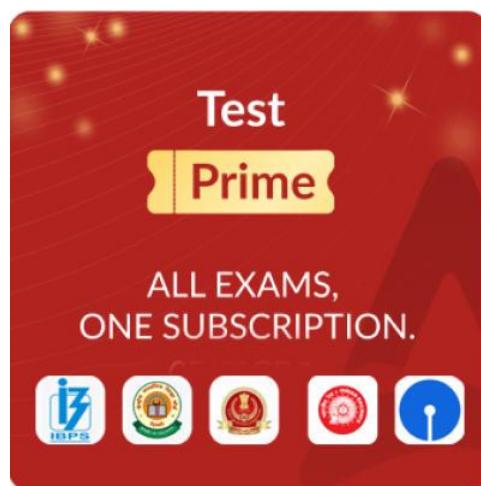
Obituaries News

- भारत में जन्मीं और सिंगापुर को अपना घर बनाने वालीं पर्यावरण लीडर कीर्तिदा मेकानी का 19 जनवरी को 66 साल की उम्र में अचानक हार्ट अटैक से निधन हो गया। "ट्री लेडी" के नाम से मशहूर, उन्होंने तीन दशकों से ज्यादा समय तक चुपचाप लेकिन मज़बूती से प्रकृति संरक्षण, सामुदायिक भलाई और सांस्कृतिक विकास के लिए काम किया। उनके काम ने सिंगापुर भर के स्कूलों, बगीचों, कला स्थलों और हरे-भरे इलाकों को छुआ।
- विश्व प्रसिद्ध बैलेंटिनो फैशन हाउस के संस्थापक बैलेंटिनो गैरावानी का 93 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन पर दुनिया भर के डिज़ाइनरों, मशहूर हस्तियों और फैशन संस्थानों ने श्रद्धांजलि दी है।
- भारत और ईस्ट बंगाल के पूर्व फुटबॉल स्टार इलियास पाशा का 22 जनवरी, 2026 को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। अपने शांत और अनुशासित खेल शैली के लिए जाने जाने वाले पाशा कर्नाटक के बेहतरीन फुटबॉलरों में से एक थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, दो बेटियां और दो बेटे हैं। भारतीय फुटबॉल समुदाय इस महान डिफेंडर के खोने का शोक मना रहा है।

Miscellaneous News

- सुनीता विलियम्स ने नासा से रिटायरमेंट लिया: भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता लिन विलियम्स 27 दिसंबर, 2025 को रिटायर हो गई, जिससे उनका 27 साल का नासा करियर खत्म हो गया। उन्होंने अंतरिक्ष में कुल 608 दिन बिताए, 9 स्पेस वॉक किए जिनका कुल समय 62 घंटे 6 मिनट था (किसी महिला के लिए सबसे

- ज्यादा), और ISS मिशन के दौरान अंतरिक्ष में पहली ऐतिहासिक मैराथन दौड़ लगाई।
- CGCA ने SAMPANN पेंशन पोर्टल को UMANG से जोड़ा: कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स के ऑफिस ने SAMPANN पेंशन सिस्टम को UMANG प्लेटफॉर्म से जोड़ा है, जिससे लगभग 4 लाख DoT पेंशनभोगी UMANG एप/वेब पोर्टल के ज़रिए PPO नंबर और लाइफ सर्टिफिकेट की वैलिडिटी देख सकेंगे, जिससे ऑफिस जाने की ज़रूरत खत्म हो जाएगी।
- GeM ने वूमेनिया पहल के सात साल पूरे किए: गवर्नर्मेंट ई-मार्केटप्लेस ने वूमेनिया पहल के 7 साल पूरे होने का जश्न मनाया, जिसमें 2 लाख महिला-नेतृत्व वाले MSEs रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने 80,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के सरकारी खरीद ऑर्डर हासिल किए हैं (GeM के कुल का 4.7%), जो महिला-स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए 3% के अनिवार्य लक्ष्य से ज्यादा है।
- IICA ने PGIP का 8वां बैच लॉन्च किया: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने पोस्ट ग्रेजुएट इनसॉल्वेंसी प्रोग्राम (PGIP) के 8वें बैच के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किए और इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) फ्रेमवर्क के तहत पेशेवर रूप से प्रशिक्षित इनसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर्स की क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए IIPI-ICAI के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए।
- DFS ने कम्पोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज लॉन्च किया: डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों (ग्रुप A, B, C) के लिए 'कम्पोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज' लॉन्च किया, जिसमें ज़ीरो-बैलेंस अकाउंट, रियायती ब्याज दरें, 2 करोड़ रुपये (हवाई दुर्घटना) और 1.5 करोड़ रुपये (व्यक्तिगत/विकलांगता) तक का व्यापक बीमा कवर शामिल है।
- CCI की 20 जनवरी, 2026 को मंजूरी: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने RBL बैंक में एमिरेट्स NBD द्वारा 74% तक शेयरधारिता के अधिग्रहण और टाटा स्टील द्वारा इंवेनी पेलेट्स में 50.01% इक्विटी के अधिग्रहण को मंजूरी दी, साथ ही बड़े पुनर्गठन के लिए JFE और JSW स्टील के बीच JV को भी मंजूरी दी।



Static Takeaways

विषय / संगठन / स्थान (पूरा नाम)	मुख्य विवरण
वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance)	केंद्रीय मंत्री – निर्मला सीतारमण (राज्यसभा – कर्नाटक) राज्य मंत्री – पंकज चौधरी (महाराजगंज, उत्तर प्रदेश)
आंध्र प्रदेश	मुख्यमंत्री – एन. चंद्रबाबू नायडू राज्यपाल – सैयद अब्दुल नज़ीर राजधानी – अमरावती रामसर स्थल – कोलेरू झील
सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM)	प्रारंभ – 2016 (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) मुख्य कार्यकारी अधिकारी – मिहिर कुमार मुख्यालय – नई दिल्ली स्थापना – 9 अगस्त 2016
नीति आयोग (NITI Aayog)	अध्यक्ष – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य कार्यकारी अधिकारी – वी. वी. आर. सुब्रह्मण्यम मुख्यालय – नई दिल्ली स्थापना – 2015
पिरामल फाइनेंस लिमिटेड	RBI-नियंत्रित NBFC (Investment & Credit Company) सहायक – Piramal Enterprises DHFL अधिग्रहण – सितंबर 2021 स्थापना – 11 अप्रैल 1984 MD & CEO – जयराम श्रीधरन मुख्यालय – मुंबई
अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ (FIDE)	अध्यक्ष – अर्कादी द्वोर्कोविच मुख्यालय – लॉज़ेन, स्विट्जरलैंड स्थापना – 1924
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	केंद्रीय मंत्री – पीयूष गोयल (मुंबई उत्तर) राज्य मंत्री – जितिन प्रसाद (पीलीभीत)
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	स्थापना – 1 अप्रैल 1935 (RBI अधिनियम, 1934) गवर्नर – संजय मल्होत्रा (26वें) मुख्यालय – मुंबई
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	केंद्रीय मंत्री – शिवराज सिंह चौहान राज्य मंत्री – रामनाथ ठाकुर (राज्यसभा – बिहार) राज्य मंत्री – भागीरथ चौधरी (अजमेर)
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD)	महानिदेशक – डॉ. मृत्युंजय महापात्र मुख्यालय – नई दिल्ली स्थापना – 1875
भारतीय तटरक्षक बल	महानिदेशक – परमेश शिवमणि मुख्यालय – नई दिल्ली स्थापना – 1977 आदर्श वाक्य – वयम् रक्षामः (हम रक्षा करते हैं)
विश्व बैंक	अध्यक्ष – अजय बंगा मुख्यालय – वॉशिंगटन डी.सी., USA स्थापना – 1944
यमन	राजधानी – सना मुद्रा – यमनी रियाल (YER)

विषय / संगठन / स्थान (पूरा नाम)	मुख्य विवरण
भारतीय सेना	थल सेनाध्यक्ष – जनरल उपेंद्र द्विवेदी मुख्यालय – नई दिल्ली स्थापना – 1895 आदर्श वाक्य – सेवा परमो धर्मः
असम	मुख्यमंत्री – हिमंता बिस्वा सरमा राज्यपाल – लक्ष्मण प्रसाद आचार्य राजधानी – दिसपुर राष्ट्रीय उद्यान – काज़ीरंगा, मानस
फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया	अध्यक्ष – श्रीनिवास पाणिग्रही (SBI) मुख्यालय – मुंबई स्थापना – 1958
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)	प्रबंध निदेशक – क्रिस्टालिना जॉर्जिवा मुख्यालय – वॉशिंगटन डी.सी. सदस्य देश – 191 स्थापना – 1944
गृह मंत्रालय	केंद्रीय मंत्री – अमित शाह राज्य मंत्री – नित्यानंद राय राज्य मंत्री – वंदी संजय कुमार
युगांडा	प्रधानमंत्री – रॉबिनाह नबांजा राजधानी – कंपाला मुद्रा – युगांडन शिलिंग (UGX)
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF)	प्रशासनिक नियंत्रण – गृह मंत्रालय नीति मार्गदर्शन – NDMA (अध्यक्ष: प्रधानमंत्री) बल – 16 बटालियन महानिदेशक – पीयूष आनंद मुख्यालय – नई दिल्ली
यूनाइटेड किंगडम (UK)	प्रधानमंत्री – कीर स्टारमर राजधानी – लंदन मुद्रा – पाउंड स्टर्लिंग (GBP)
वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन	अध्यक्ष – प्रो. जगदीश मुखी मुख्यालय – नई दिल्ली स्थापना – 2021
ગुજરात	मुख्यमंत्री – ભૂપેન્દ્ર પટેલ राज्यपाल – આचार्य દેવવ્રત राजधानી – ગાંધીનગર રામસર સ્થળ – નલસરોવર, વડવાના
મूડीज़ रेटिंग्स	अध्यक्ष – માઇકલ વેસ્ટ मुख्यालय – ન્યૂયૉર્ક स्थापना – 1909
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)	अध्यक्ष – રવनीत कौર मुख्यालय – नई दिल्ली स्थापना – 2003
संयुक्त अરब अमीरात (UAE)	राष्ट्रपति – शेikh મોહમ्मद બિન જાયદ અલ નાહયાન राजधानી – અબુ ધાબી मुद्रा – રિહમ (AED)
अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)	મहानिदेशक – ગિલ્બર્ટ એફ. હૌનાબો मुख्यालय – જિનેવા सदस्य દेश – 187 स्थापना – 1919

विषय / संगठन / स्थान (पूरा नाम)	मुख्य विवरण
नंबियो (Numbeo)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी – म्लाडेन एडामोविच मुख्यालय – बैलग्रेड, सर्विया स्थापना – 2009
नासा (NASA)	प्रशासक – जारेड आइज़ैकमैन मुख्यालय – वॉशिंगटन डी.सी. स्थापना – 1958
SIDBI	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – मनोज मित्तल मुख्यालय – लखनऊ स्थापना – 1990
BHASHINI	मंत्रालय – इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय CEO – अमिताभ नाग स्थापना – 2022
विश्व आर्थिक मंच (WEF)	अध्यक्ष एवं CEO – बोरगे ब्रेंडे मुख्यालय – जिनेवा, स्विट्जरलैंड स्थापना – 1971
उत्तर प्रदेश	मुख्यमंत्री – योगी आदित्यनाथ राज्यपाल – आनंदीबेन पटेल राजधानी – लखनऊ वन्यजीव अभयारण्य – चंबल, कैमूर

